

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एकल पीठ सिविल रिट याचिका सं 15257/2021

हाथी सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी: गाँव
बेलवा खत्री, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

----- याचिकाकर्ता

बनाम

भेराराम पुत्र श्री छगनाराम, निवासी ग्राम बेलवार खत्रीया, तहसील
बालेसर, जिला जोधपुर (राज)

----- उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (गण) के लिए श्री ओ पी मेहता

उत्तरदाता(गण) के लिए श्री जी आर पुनिया, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री महावीर भंवरिया द्वारा सहायता प्राप्त

निर्णय आरक्षित करने की दिनांक: 24/11/2021

निर्णय उद्घोषणा की दिनांक: 06/12/2021

न्यायाधिपति दिनेश मेहता

निर्णय

रिपोर्टबल

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र क्षेत्र को याचिकाकर्ता द्वारा, जोधपुर जिले के विद्वान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांकित 27.07.2021 के आदेश को चुनौती देने के उद्देश्य से लागू किया गया है (यहाँ 'चुनाव न्यायाधिकरण' या 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित)।
2. इसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर चर्चा करद्वारा से पहले, मामले के तथ्यात्मक परिदृश्य को देखना उचित होगा।
3. प्रत्यर्थी-चुनाव याचिकाकर्ता ने राजस्थान पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 (इसके बाद '1994 के नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 80 के साथ पठित राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की खंड 43 (इसके बाद '1994 के अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत एक चुनाव याचिका दायर की। अन्य बातों के साथ-साथ चुनाव याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता- रिटर्न उम्मीदवार और प्रतिवादी-चुनाव याचिकाकर्ता ने ग्राम पंचायत बेलवा खत्री के सरपंच पद के लिए अपने नामांकन पत्र जमा कर दिए थे। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के अलावा, कई अन्य व्यक्तियों ने भी अपने नामांकन पत्र जमा किए थे, जिनमें से

कुछ ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए थे, जबकि उनमें से कुछ के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए थे। परिणामस्वरूप केवल दो उम्मीदवार, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी, सरपंच पद के लिए प्रतियोगिता में बने रहे।

4. चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा से 17.01.2020 को आयोजित किया गया था, और उसी दिन वोटों की गिनती की गई और परिणाम घोषित किया गया। इसमें याचिकाकर्ता को रिटर्न उम्मीदवार घोषित किया गया था।

5. चुनाव याचिका में दिए गए मतों का विवरण नीचे दिया गया है:-

कुल चुनाव पत्र :2917

वोट डाले गए :2446

चुनाव-याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त मत:- 1174

रिटर्न उम्मीदवार द्वारा प्राप्त:- 1242 मत:

नोटा:- :30.

6. चुनाव याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के चुनाव को एकमात्र इस आधार पर चुनौती दी कि वह 1994 के अधिनियम की खंड 19 (ए) में प्रदान किए गए अपेक्षित आयु मानदंडों को पूरा नहीं करता है।- 'उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए'।

7. वर्तमान याचिकाकर्ता (चुनाव याचिका में गैर-याचिकाकर्ता) ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन दायर किया और न्यायाधिकरण से चुनाव याचिका को अस्वीकार करने का अनुरोध किया, क्योंकि चुनाव याचिका के ज्ञापन में दायर सत्यापन 1994 के नियमों के नियम 83 के अनुसार नहीं था। याचिकाकर्ता द्वारा इस प्रकार दायर आवेदन को न्यायाधिकरण द्वारा अपने दिनांक 18.08.2020 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

8. न्यायाधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसे एस. बी. सिविल रिट याचिका 1137/2020 के रूप में पंजीकृत किया गया था। रिट याचिका की दलीलों के दौरान, प्रतिवादी के वकील ने हालांकि यह स्वीकार किया कि सत्यापन दोषपूर्ण था, फिर भी प्रस्तुत किया कि इस तरह का दोष एक उपचार योग्य दोष है और R.P मोइदुद्दी बनाम P.T। कुंजू मोहम्मद, ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 388 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में है। अतः उन्हें इसका संशोधन करने की अनुमति दी जाए।

9. इस प्रकार किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए, 05.04.2021 पर, याचिकाकर्ता की पिछली रिट याचिका का निम्नलिखित शर्तों में निपटारा किया गया:-

"विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा की गई इस तरह की स्पष्ट प्रस्तुति पर, वर्तमान प्रतिवादी याचिका का निपटारा आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार सख्ती से किए गए सत्यापन में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पुनिया द्वारा दिए गए बयान के अनुसार दोष को ठीक करने की स्वतंत्रता के साथ किया जाता है। यदि दोषों को ठीक करने के बाद, याचिका के साथ-साथ दस्तावेजों में कोई दोष बना रहता है, तो याचिकाकर्ता इसे विचारण न्यायालय के समक्ष उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।"

10. प्रत्यर्थी-चुनाव याचिकाकर्ता ने बदले में, "आदेश VI नियम 15 के के साथ धारा 151 सी. पी. सी." के शीर्षक के साथ, 09.04.2021 दिनांकित एक आवेदन दायर किया। पूर्ववर्ती रिट याचिका में पारित दिनांक 05.04.2021 के आदेश का संदर्भ देते हुए, प्रतिवादी ने निर्वाचन याचिका के लिए एक सत्यापन और दस्तावेजों का सत्यापन करते हुए दूसरा सत्यापन प्रस्तुत किया और प्रार्थना की कि उन्हें हस्ताक्षर करके दस्तावेजों (जो पहले से ही चुनाव याचिका के साथ दायर किए गए थे) को सत्यापित करने की अनुमति दी जाए।

11. प्रतिवादी-चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन का रिटर्निंग उम्मीदवार (यहां याचिकाकर्ता) द्वारा विरोध किया गया था और इसमें

एक विस्तृत जवाब दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि आवेदन, जो प्रतिवादी द्वारा संहिता के आदेश VI नियम 15 के तहत दायर किया गया है, अक्षम था क्योंकि संहिता के आदेश VI नियम 17 के तहत अभिवचनों में संशोधन का प्रावधान दिया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह जानबूझकर संहिता के आदेश VI नियम 17 के प्रावधानों की कठोरता से बाहर निकलने के लिए किया गया था, जो मुकदमा शुरू होने के बाद संशोधन के अधिकार को प्रतिबंधित करता है।

12. गैर-याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ता) द्वारा यह भी तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिकाकर्ता को 'कानून के अनुसार' दोषों को ठीक करने की अनुमति दी थी और इसे उस तरीके से नहीं किया जा सकता है जिस तरह से करने का प्रयास किया गया था।

13. प्रतिद्वंद्वी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी के आवेदन दिनांक 09.04.2021 को इस टिप्पणी के साथ अनुमति दी कि सत्यापन अभिवचन का हिस्सा नहीं है और इसे कानून के सही प्रावधान (संहिता के आदेश VI नियम 15) के तहत दायर किया गया है। नतीजतन, सत्यापन और शपथ पत्र दोनों को रिकॉर्ड पर ले लिया गया और चुनाव-याचिकाकर्ता को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई, जो चुनाव याचिका के साथ दायर किए गए थे।

14. उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ओम मेहता ने जोरदार तर्क दिया कि न्यायाधिकरण याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज करने में कानून की एक स्पष्ट त्रुटि में पड़ गया है कि एक नया सत्यापन दाखिल करने के उद्देश्य से, संहिता के आदेश VI नियम 15 के प्रावधान लागू थे। उनके अनुसार, सत्यापन अभिवचन का एक अभिन्न अंग है और इसलिए, इस तरह के उद्देश्य के लिए सक्षम प्रावधान आदेश VI का नियम 17 है न कि नियम 15।

15. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संहिता के आदेश VI नियम 15 में शिकायत या लिखित बयान के आधार पर सत्यापन का प्रावधान है और यदि कोई संशोधन किया जाना है, तो उसे केवल संहिता के आदेश VI नियम 17 के प्रावधानों के तहत ही मांगा जा सकता है और इसलिए, नए सिरे से सत्यापन की अनुमति देने के अनुरोध पर विचार करते समय, न्यायालय को संहिता के आदेश VI नियम 17 के लिए लागू सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए।

16. उन्होंने कहा कि यदि प्रतिवादी (चुनाव-याचिकाकर्ता) ने संहिता के आदेश VI नियम 17 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया होता, तो उनका आवेदन संहिता के आदेश VI के नियम 17 के प्रावधान से प्रभावित होता। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि विवाद्यक तैयार किए गए हैं और उसके परिणामस्वरूप मुकदमा शुरू हो गया है, इसलिए प्रतिवादी द्वारा दायर

संशोधन के लिए आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि इसमें कोई दावा नहीं किया गया है कि उचित परिश्रम के बावजूद, वह सत्यापन में मौलिक खामियों को दूर नहीं कर सके।

17. उनके अनुसार, परंतुक में प्रयुक्त "उचित परिश्रम" अभिव्यक्ति का बहुत महत्व है और वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, प्रतिवादी उचित परिश्रम का अनुरोध भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने न केवल आकस्मिक रूप से चुनाव याचिका दायर की थी, बल्कि इस तर्क के साथ मामले को उच्च न्यायालय तक भी चुनौती दी थी, जो कि सत्यापन के क्रम में था। उन्होंने कहा कि यह केवल तभी हुआ जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की शरण लेते हुए दोष को ठीक करने के लिए स्वतंत्रता मांगी गई।

18. श्री मेहता ने यह भी संकेत दिया कि विषय आवेदन के साथ, प्रतिवादी ने इसके समर्थन में एक शपथ पत्र दायर किया है. जबकि उन्हें 1994 के नियमों के नियम 83 के संदर्भ में सत्यापन दाखिल करने की आवश्यकता थी। इस तथ्य की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित करते हुए कि न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी के आवेदन की अनुमति दी है और आवेदन के साथ अलग से दायर सत्यापन को रिकॉर्ड पर लिया है, यह महसूस किए बिना कि याचिका के साथ दायर किया गया पहले का दोषपूर्ण सत्यापन रिकॉर्ड में बना हुआ है, उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि

बाद का सत्यापन (आवेदन के साथ दायर) कहां रखा जाएगा। उनके अनुसार, कमी अभी भी बनी हुई है क्योंकि 1994 के नियमों के नियम 83 के अनुसार, अभिवचन को हमेशा अपने आधार पर सत्यापन की आवश्यकता होती है।

19. श्री जी आर पुनिया प्रतिवादी (चुनाव-याचिकाकर्ता) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, पुनिया ने सबसे पहले संहिता के आदेश VI नियम 3 के प्रावधान की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि यह परिशिष्ट 'ए' में विभिन्न प्रपत्रों का प्रावधान करता है और इसे ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि परिशिष्ट 'ए' में किसी भी प्रकार का सत्यापन नहीं है जो स्पष्ट रूप से बताता है कि सत्यापन अभिवचन का हिस्सा नहीं है।

20. उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव याचिका के साथ दायर सत्यापन में त्रुटि को सुधारने के उद्देश्य से और दस्तावेजों के लिए सत्यापन दाखिल करने के उद्देश्य से, प्रासंगिक और लागू प्रावधान था, संहिता का आदेश VI नियम 15 और याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज करने के लिए चुनौती के तहत आदेश कि संहिता के आदेश VI नियम 17 के तहत एक आवेदन द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता है, यह न्यायसंगत और उचित है।

21. संहिता के आदेश VI नियम 1 में दी गई "अभिवचन" शब्द की परिभाषा को पढ़ते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभिवचन का अर्थ केवल वाद और लिखित कथन है न कि सत्यापन। उनके अनुसार, सत्यापन जो अभिवचनों का हिस्सा नहीं है, उसे आदेश VI नियम 15 के तहत दायर आवेदन के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। संहिता की नियम 15 या संहिता की धारा 151 में निहित न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के तहत, और संहिता के आदेश VI नियम 17 के प्रावधानों का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

22. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अदालत को संहिता के आदेश VI के नियम 2 के प्रावधानों द्वारा से लिया और बताया कि अभिव्यक्ति "अभिवचन" सत्यापन का कोई संदर्भ नहीं देती है; अपने रुख को साबित करने के लिए कि सत्यापन शिकायत, लिखित बयान या यहां तक कि अभिवचन का हिस्सा नहीं है।

23. उनकी उपरोक्त दलीलों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संहिता की खंड 151 न्यायालय को न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उचित आदेश पारित करने के लिए अंतर्निहित और असीमित शक्तियां प्रदान करती है। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि यह न्यायालय पहले ही प्रतिवादी (चुनाव याचिकाकर्ता) को दोषों को ठीक करने की स्वतंत्रता दे चुका है, इसलिए न्यायाधिकरण से यह

आवश्यक था कि वह तुच्छ तकनीकीताओं से प्रभावित हुए बिना उसे ऐसा करने की अनुमति दे।

24. अपने इस रुख पर कायम रहते हुए कि विचाराधीन आवेदन सही प्रावधान के तहत दायर किया गया था, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने विकल्प में कहा कि प्रावधान का केवल गलत उल्लेख किसी पक्ष के अधिकार को पराजित नहीं कर सकता है, अगर ऐसी शक्ति कहीं और पाई जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए, श्याम कुमार बनाम सुरेंद्र कुमार गोयल 2017 (1) डब्ल्यू. एल. सी. 651 (यू. सी.) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया था।

25. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मेहता ने पंकजभाई रमेशभाई जलवाडिया जेठाभाई कलाभाई जलवाडिया (मृतक) (2017) 9 एस. सी. सी. 700 (पैरा 16) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यह कानून की एक स्थिर स्थिति है कि यदि किसी काम को एक विशेष तरीके से करने की आवश्यकता है, तो उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए।

26. संहिता के आदेश VI के नियम 3 की भाषा के आधार पर श्री पुनिया की दलीलों का जवाब देते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि केवल इसलिए कि सत्यापन का रूप परिशिष्ट "ए" में निर्धारित नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता है कि सत्यापन अभिवचन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि

संहिता के आदेश VI के नियम 3 की भाषा स्पष्ट रूप से बताती है कि यह समावेशी है और संपूर्ण नहीं है।

27. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण को याचिकाकर्ता की मूल आपत्ति को स्वीकार करना चाहिए था कि याचिका के सत्यापन और दस्तावेजों के संबंध में दोष को विषय आवेदन के बल पर ठीक नहीं किया जा सकता है, जो जानबूझकर संहिता के आदेश VI के नियम 17 के तहत दायर नहीं किया गया था।

28. सुना गया।

29. मान लीजिए, जिन दस्तावेजों को चुनाव याचिका के ज्ञापन के साथ सत्यापन और सत्यापन द्वारा समर्थित नहीं किया गया था, (जैसा कि दायर किया गया था) वे 1994 के नियमों के नियम 82 के प्रावधान के अनुरूप नहीं थे और इन दोषों को इस न्यायालय द्वारा R.P मोड़दुती (ऊपर) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में ठीक करने की अनुमति दी गई थी। ।

30. लेकिन फिर, सवाल यह है कि इन दोषों को कैसे ठीक किया जाए?

31. पहले के सत्यापन में, प्रतिवादी ने एक सामान्य टिप्पणी दी थी कि याचिका का पैरा No.1 से 17 उसकी व्यक्तिगत जानकारी और कानूनी सलाह के आधार पर सत्य और सही है। वर्तमान याचिकाकर्ता ने इस

तरह के सत्यापन पर आपत्ति जताई, क्योंकि यह संहिता के आदेश VI के नियम 15 के उप-नियम (2) की आवश्यकता के अनुरूप नहीं था।

32. प्रदत्त स्वतंत्रता को आगे बढ़ाते हुए, प्रतिवादी ने एक सत्यापन दायर किया जो दर्शाता है कि पैरा No.1 से 13 उसके ज्ञान के लिए सही और सही हैं और पैरा No.1 4 से 17 को कानूनी सलाह के आधार पर सही माना जाता है। लेकिन कहा गया कि सत्यापन एक आवेदन के साथ दायर किया गया था जिसका शीर्षक था "संहिता के आदेश VI नियम 15 सपठित धारा 151 सी. पी. सी.।"

33. यह न्यायालय न्यायाधिकरण के इस दृष्टिकोण को बरकरार रखने में असमर्थ है कि सत्यापन अभिवचन का हिस्सा नहीं है और यदि सत्यापन में कोई संशोधन करने की आवश्यकता है, तो संहिता का आदेश VI नियम 15 प्रासंगिक प्रावधान है।

34. इस न्यायालय की राय में, संहिता के आदेश VI नियम 15 में आदेश दिया गया है कि प्रत्येक अभिवचन को पक्ष द्वारा स्वतः सत्यापित किया जाएगा। मेरे विचार से उक्त प्रावधान केवल एक सक्षम प्रावधान है, जो भी आदेश VI का एक अभिन्न अंग है, जिसका अध्याय शीर्षक "सामान्य रूप से दलीलें" है। नियम 15 आवश्यकता के लिए प्रावधान करता है, इसलिए सत्यापन की पूर्व-आवश्यकताएं भी, इसलिए, इस न्यायालय की राय में, सत्यापन को कुछ भी नहीं माना जा सकता है, लेकिन

अभिवचन का एक हिस्सा, अकेले खड़े होकर, एक सत्यापन की कोई पहचान नहीं है या बहुत कम है, जिसका कोई महत्व नहीं है।

35. यदि श्री पुनिया, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, के तर्क को स्वीकार किया जाना था कि सत्यापन में संशोधन करने का आवेदन केवल संहिता के आदेश VI नियम 15 के तहत बनाए रखा जा सकता है, तो एक वाद को संहिता के आदेश VII नियम 1 के तहत संशोधित किया जा सकता है और इसलिए संहिता के आदेश VIII नियम 1 के तहत एक लिखित कथन हो सकता है क्योंकि आदेश VII और आदेश VIII का नियम 1 क्रमशः निर्धारित करता है कि वाद में क्या निहित होना चाहिए और लिखित कथन में क्या निहित होना चाहिए जैसा कि सत्यापन के संबंध में आदेश VI का नियम 15 करता है। अन्यथा, एक अधिनियम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी. नियम 17 के रूप में संशोधन के लिए अलग प्रावधान, यहां तक कि वाद और लिखित कथन के लिए भी।

36. यह मुद्दा कि क्या सत्यापन अभिवचन का एक हिस्सा है और क्या आदेश VI नियम 17 के प्रावधान को सत्यापन में संशोधन के लिए सेवा में लगाया जा सकता है, दिल्ली उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष आया। हालाँकि, दोनों उच्च न्यायालयों के विचार पूरी तरह से विपरीत हैं, लेकिन फिर भी तथ्यों के संक्षिप्त विवरण के साथ अपद्वारा निर्णयों में की गई व्याख्या को देखना लाभदायक होगा।

37. संक्षेप में कहा जाए तो तथ्य जोतिराम शिवा पाटिल और अन्य बनाम द्वारकाबाई यशवंत मर्दाने और अन्य [2012 (4) बम अन्य 190; एम. ए. एन. यू./एम. एच./1590/2011] के मामले से संबंधित हैं कि उसमें प्रतिवादियों ने अन्य प्रतिवादियों को लिखित बयान पर हस्ताक्षर करने और संहिता के आदेश VI के संदर्भ में सहायक शपथ पत्र दायर करने की अनुमति देने और सत्यापन खंड को सही करने के लिए भी विचारण के समक्ष आवेदन दायर किए। उक्त आवेदन खारिज कर दिए गए और तदनुसार उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई जिसमें प्रत्यर्थियों-वादियों की आपत्ति थी कि सत्यापन खंड को किसी भी तरह से अभिवचन नहीं कहा जा सकता है; यह तर्क दिया गया कि संहिता के आदेश VI नियम 17 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित निर्णयों पर याचिकाकर्ताओं-प्रतिवादियों की निर्भरता गलत थी और संहिता के आदेश VI नियम 17 का संदर्भ एक गलत नाम था क्योंकि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता उक्त आवेदनों के माध्यम से वास्तव में सी. पी. सी. की धारा 153 के तहत अपील न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर रहे थे। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित करते हुए उक्त आपत्ति को स्वीकार कर लिया:

"12. हालाँकि ट्रायल कोर्ट इस पर आगे बढ़ चुका है
आधार यह है कि उक्त प्रदर्श 43 और प्रदर्श 43 ए को सी.

पी. सी. के आदेश 6 नियम 17 का आह्वान करते हुए दायर किया गया है। मेरे विचार में, सी. पी. सी. के आदेश 6 नियम 1 और आदेश 7 नियम 1 को देखते हुए उक्त प्रावधान का संदर्भ गलत है। अभिवचन पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन खंड पर हस्ताक्षर करने की अनुमति को किसी भी कल्पना के विस्तार से अभिवचनों का संशोधन नहीं कहा जा सकता है। अभिवचनों पर हस्ताक्षर और सत्यापन को केवल उनके समर्थकों द्वारा उक्त अभिवचनों को प्रमाणित करने के लिए कहा जा सकता है। इसलिए, निचली अदालत ने सी. पी. सी. के आदेश 6 नियम 17 को स्वीकार करने में गलती की है। तथापि, इससे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोई भौतिक अंतर नहीं पड़ेगा कि निचली अदालत को सी. पी. सी. की खंड 153 के तहत कार्यवाही में किसी भी दोष या त्रुटि के सुधार की अनुमति देने की शक्तियां पर्याप्त रूप से समाप्त कर दी गई हैं ताकि निचली अदालत के समक्ष वास्तविक प्रश्न के निर्धारण को सुविधाजनक बनाया जा सके।"

38. एफ. एम. सी. निगम और अन्य के मामले में बनाम एनएटीसीओ फार्मा लिमिटेड [2020 आईवीएडी (दिल्ली) 553;

MANU/DE/1380/2020] अदालत ने अनुमति दी I.A नंबर 4274/2020 और 5209/2020 वादी द्वारा संहिता के आदेश VI नियम 17 के तहत दायर किया गया। I.A नंबर 4274/2020 ने I.A विचाराधीनता रहने के दौरान वाद के नीचे सत्यापन में संशोधन करने की मांग की। नंबर 4274/2020 वादी ने I.A को प्राथमिकता दी। नंबर 5290/2020 में प्रस्तावित संशोधित सत्यापन में हुई त्रुटि को सुधारने के लिए एक बार फिर से वाद के नीचे दिए गए सत्यापन में संशोधन करने की मांग की गई है। नंबर 4274/2020 न्यायालय ने उक्त आवेदनों को स्वीकार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"23. उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि सत्यापन में, शिकायत के नीचे, और शिकायत के साथ सत्य कथन के पैरा 3 में संशोधन, जैसा कि I.A में प्रस्तावित है। 5209/2020, को अनुमति देने की आवश्यकता है। मामले में मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है। प्रतिवादी ने एक बार भी सामग्री को रिकॉर्ड में नहीं रखा है, या किसी भी प्रस्तुति को आगे नहीं बढ़ाया है, जो यह इंगित करता है कि संशोधनों की अनुमति दी गई है, जैसा कि वादी द्वारा माँगा गया है, प्रतिवादी के प्रति अपूरणीय पूर्वाग्रह का परिणाम होगा। उस स्थान और तिथि

के संबंध में पाठ, जब वाद का सत्यापन किया गया था, और वाद में विभिन्न अनुच्छेदों की सामग्री का दावा करने का आधार, सही और सही होने के लिए, प्रतिवादी की जानकारी में हैं और यदि, जैसा कि मूल रूप से दायर किया गया था, कोई त्रुटि, चूक, उसके संबंध में मौजूद थी, तो दोष को सुधारने के लिए, न्यायालय की अधिकार क्षेत्र का आह्वान करके, अभिवचनों में संशोधन की अनुमति देने के लिए, किसी भी तरह से कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है। प्रक्रियात्मक न्यायाधीश को कड़ा नहीं ठहराया जा सकता है। यह निवेदन कि संशोधनों का "पूरे मामले पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव" था, "प्रतिपरीक्षा पर एक गंभीर प्रभाव" और "परीक्षण प्रक्रियाओं के अनुपालन के किसी भी संभव पर प्रतिकूल प्रभाव", स्पष्ट रूप से, बहुत कम तथ्य के साथ केवल तर्क हैं। यह निवेदन कि सत्य कथन के पैरा 3 में संशोधनों को अनुमति देने से, और वाद के नीचे सत्यापन में, प्रतिपरीक्षा, या परीक्षण प्रक्रियाओं के उचित अनुपालन में बाधा आएगी, पूरी तरह से समझ से बाहर है; महत्वपूर्ण रूप से, हालांकि इन तर्कों को लिखित प्रस्तुतियों के पैरा 2 में आगे बढ़ाया गया है, जिसे प्रतिवादी द्वारा इन आवेदनों पर निर्णय

सुरक्षित रखने के बाद रिकॉर्ड में रखा गया है, श्री साई दीपक ने अपने अनुभव के साथ तर्क के दौरान ऐसा आग्रह नहीं किया।केवल यह तथ्य कि सत्यापन और सत्य के कथन में खामियों के परिणामस्वरूप संशोधन मांगे गए थे, इस न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान प्रतिवादी द्वारा इंगित किया गया था, संशोधन के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने का आधार नहीं बना सकता है।हर समय, यह याद रखना होगा कि संशोधन की अनुमति देने की शक्ति अदालत के कर्तव्य को आगे बढ़ाने के लिए है, जो उसके समक्ष गुण-दोष पर निर्णय लेने के लिए है, तकनीकी विचारों से अप्रभावित है और इसलिए, इसका उपयोग किया जाना आवश्यक है।संशोधनों को अस्वीकार करना, जैसा कि माँगा गया है, और मुकदमा को दोषों के साथ मुकदमे में आगे बढ़ने की अनुमति देना, मुकदमा के नीचे के सत्यापन में, और सत्य के कथन के संबंधित पैराग्राफ में, अपरिवर्तित रहना, बहुत ही अनाज के खिलाफ जाएगा और आदेश VI नियम 17 का दर्शन। इसलिए इस तरह के दृष्टिकोण से लापरवाही से बचना चाहिए।"

39. उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए रुख जहां तक वाद के तहत सत्यापन के उपचार का संबंध है, उनमें विरोधाभास है, क्योंकि पूर्व का मानना है कि वाद के नीचे सत्यापन आदेश VI नियम 17 के तहत परिकल्पित अभिवचनों के दायरे के भीतर है, जबकि बाद वाला इसे आदेश VI नियम 17 के तहत परिकल्पित अभिवचनों के दायरे से बाहर मानता है।

40. इस न्यायालय के अनुसार, न्यायालयों को योग्यता के आधार पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करने और न्याय के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए, अभिवचनों में संशोधन के उद्देश्य से आदेश VI में नियम 17 जोड़ा गया था। सुधार की अनुमति देने के लिए शक्ति का एकमात्र स्रोत केवल संहिता की खंड 151 के साथ पठित आदेश VI के नियम 17 में पाया जा सकता है न कि संहिता के आदेश VI नियम 15 में।

41. अब दूसरा सवाल आता है, क्या पहले के सत्यापन में दोष का उपचार संहिता के आदेश VI के नियम 17 के प्रावधान के नेतृत्व में है?

42. इस प्रश्न को शुरू करने से पहले, संहिता के आदेश VI के नियम 17 के प्रावधानों पर एक नज़र डालना बेहतर होगा, जिसे यहां पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

"17. अभिवचनों का संशोधन- न्यायालय में हो सकता है प्रतिवादी का कोई भी चरण किसी भी पक्ष को अपनी दलीलों को इस तरह से और ऐसी शर्तों पर बदलने या संशोधित करने की अनुमति देता है जो न्यायसंगत हो, और ऐसे सभी संशोधन किए जाएंगे जो पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों का निर्धारण करने के उद्देश्य से आवश्यक हों।

बशर्ते कि संशोधन के लिए कोई आवेदन नहीं होगा

मुकदमा शुरू होने के बाद अनुमति दी जाएगी, जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि उचित परिश्रम के बावजूद, पक्षकार मुकदमा शुरू होने से पहले मामले को नहीं उठा सकता था।"

* जोर दिया गया।

43. यह ध्यान दें उचित है कि संहिता के आदेश VI का नियम 17 अपने मुख्य भाग में परंतुक की तुलना में अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग करता है। मुख्य प्रावधान "उसकी दलीलों को बदलने या संशोधित करने के लिए" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, जबकि परंतुक में, अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है-"संशोधन के लिए कोई आवेदन नहीं"।

44. 'परिवर्तन' और 'संशोधन' शब्दों को पढ़ने से पहले, न्यायशास्त्र में उक्त शब्दों की विभिन्न परिभाषाओं और कानूनी व्यवहार के बारे में संक्षेप में जानकारी देना उचित होगा।

45. ब्लैक का कानून शब्दकोश

"बदल देते हैं। बदलाव करना; संशोधित करना; कुछ हद तक बदलना; पूरी तरह से नई चीज़ को प्रतिस्थापित किए बिना या प्रभावित चीज़ की पहचान को नष्ट किए बिना कुछ तत्वों या अवयवों या विवरणों को बदलना। आंशिक रूप से बदलना। एक या अधिक मामलों में परिवर्तन करना, लेकिन वस्तु के अस्तित्व या पहचान के विनाश के बिना परिवर्तन करना; बढ़ाना या घटाना।

परिवर्तन; संशोधन; परिवर्तन देखें।

परिवर्तन। भिन्नता; परिवर्तन; अलग बनाना। किसी वस्तु का एक रूप या राज्य से दूसरे रूप में परिवर्तन; किसी वस्तु की पहचान को नष्ट किए बिना उसे उससे अलग बनाना।

परिवर्तन देखें। एक उपकरण पर किया गया कार्य जिसके द्वारा इसका अर्थ या भाषा बदल दी जाती है। कानूनी प्रभाव में अलग भाषा, या पक्षों के अधिकारों, हितों या दायित्वों

में परिवर्तन। यह वाद्य के शब्दों, अर्थ, भाषा या विवरण में कुछ बदलाव लाता है। यह शब्द किसी भी परिवर्तन पर ठीक से लागू नहीं होता है जिसमें व्यावहारिक रूप से नए दस्तावेज़ का प्रतिस्थापन शामिल होता है। एक बदलाव इसे सामग्री कहा जाता है जब यह दस्तावेज़ में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करता है, या संभवतः प्रभावित कर सकता है।"

"संशोधन करें। सुधार करने के लिए। दोषों या दोषों को स्थानांतरित करके बेहतर के लिए बदलना। बदलने के लिए, सही करें, संशोधित करें। संशोधन बेहतर के लिए बदलना या संशोधित करना। संशोधन, विलोपन या जोड़कर परिवर्तन करना।

अभ्यास करें और विनती करें। किसी भी प्रक्रिया, अभिवचन, या कानून में कार्यवाही, या समानता में की गई त्रुटि का सुधार, और जो या तो निश्चित रूप से, या पक्षों की सहमति से, या उस न्यायालय में प्रस्ताव पर किया जाता है जिसमें कार्यवाही लंबित है। फेड के तहत आर. सिविल पी., अभिवचनों में कोई भी परिवर्तन, हालांकि आवश्यक रूप से एक सुधार नहीं है, जिसे एक

पक्ष एक उत्तरदायी अभिवचन दिए जाने से पहले किसी भी समय निश्चित रूप से एक बार पूरा कर सकता है। इस तरह का संशोधन अभिवचनों को साक्ष्य के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है। नियम 15 (ए), (बी)। संशोधन मूल अभिवचन से संबंधित है यदि इसका विषय निर्धारित लेनदेन से उत्पन्न हुआ है या मूल अभिवचन में निर्धारित करने का प्रयास किया गया है।"

46. वेबस्टर्स अंग्रेजी शब्दकोश

"बदलते हैं। 1. किसी विशेष में आकार, शैली, पाठ्यक्रम या इस तरह के रूप में अलग करना; संशोधित करना: एक कोट को बदलना; एक वसीयत को बदलना; पाठ्यक्रम को बदलना। 2. कैस्ट्रेट या जासूसी करना। 3. बदलना; अलग या संशोधित होना।"

"ठीक कीजिए। 1. (प्रस्ताव, विधेयक, संविधान, आदि) में परिवर्तन, संशोधन, पुनर्व्याख्यान, या जोड़ना या घटाना। औपचारिक रूप से

प्रक्रिया: कांग्रेस प्रस्तावित कर विधेयक में संशोधन कर सकती है। 2.

बेह्तरी के लिए बदलना; सुधार:अपने तरीकों को बदलना।

3. दोषों को दूर करना या सुधारना; सुधारना।4. स्वयं में सुधार करके आगे बढ़ना या बेहतर बनना:वह दिन में सुधार करता है

एक दिन।"

47. 'परिवर्तन' और 'संशोधन' अभिव्यक्ति में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है।'परिवर्तन' शब्द का अर्थ है संशोधन या परिवर्तन। शरीर में परिवर्तन को सामने लाए बिना; जबकि अभिव्यक्ति 'संशोधन' का एक व्यापक अर्थ और बड़ा दायरा है, जिसका अर्थ है और इसमें एक परिवर्तन शामिल है, जो पर्याप्त हो सकता है।एक संशोधन में हमेशा एक परिवर्तन शामिल होता है लेकिन एक परिवर्तन जरूरी नहीं कि संशोधन के बराबर हो।

48. परंतुक को सावधानीपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि संशोधन के लिए आवेदन की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता कि उचित परिश्रम के बावजूद, ऐसा पक्ष मुकदमा शुरू होने से पहले मामले को नहीं उठा सकता था।

49. इस न्यायालय के अनुसार, परंतुक उन मामलों से निपटने के लिए है, जहां एक पक्ष नए तथ्यों या नए आधारों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए अभिवचनों में संशोधन करना चाहता है।यही कारण है कि प्रतिबंधात्मक

दायरे वाले परंतुक को अभिव्यक्ति का उपयोग करके कहा गया है-"कि उचित परिश्रम के बावजूद, पक्ष मुकदमा शुरू होने से पहले इसे नहीं उठा सकता था।"

50. दूसरे शब्दों में, परंतुक तब लागू होता है जब कोई पक्ष इस तरह से अभिवचन में संशोधन करना चाहता है कि एक नया तथ्य या नया आधार पेश किया जाए और उस स्थिति में, पक्ष को न्यायालय को संतुष्ट करना होता है कि उचित परिश्रम के बावजूद ऐसा मामला मुकदमे के शुरू होने से पहले नहीं उठाया जा सका।

51. जबकि, उन मामलों में जहां कोई पक्ष अभिवचन में परिवर्तन करना चाहता है या दोष (ओं) को ठीक करना चाहता है, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं/नहीं हैं या ऐसे मामले जिनमें सुधार/परिवर्तन असंगत तथ्यों/मामलों या विवरण शामिल हैं, न तो संहिता के आदेश VI के नियम 17 का परंतुक लागू होता है और न ही किसी पक्ष को देरी या उचित परिश्रम का कारण दिखाने की आवश्यकता होती है। मेरे बारे में इस दृष्टिकोण को इस परंतुक में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति 'उचित परिश्रम' से बल मिलता है, जिसके बाद 'मामले को नहीं उठाया जा सकता था'।

52. इस बात का कोई खंडन नहीं है कि दस्तावेजों के समर्थन में सत्यापन अनुपस्थिति था और आगे शिकायत के साथ सत्यापन 1994 के नियमों के नियम 82 के अनुसार नहीं था, केवल दो दोष थे, और उन

दोनों को न केवल उपचार योग्य माना गया था, बल्कि याचिकाकर्ता की पिछली पारी में इस न्यायालय द्वारा ठीक करने की अनुमति भी दी गई थी।

53. इस न्यायालय के आदेश में उपयोग की गई 'दोष का इलाज' अभिव्यक्ति से ही पता चलता है कि यह 'संशोधन' के दायरे में नहीं आती है, क्योंकि प्रतिवादी-चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा कोई नया तथ्य या आधार पेश करने की मांग नहीं की गई थी।

54. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, इस न्यायालय का विचार है कि यद्यपि चुनाव न्यायाधिकरण प्रत्यर्थी-चुनाव याचिकाकर्ता को संहिता की खंड 151 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों में दोष को ठीक करने की अनुमति दे सकता था, फिर भी यदि संहिता के कुछ प्रावधानों का सहारा लिया जाना है, तो यह संहिता के आदेश VI नियम 17 की रूपरेखा के भीतर किया जाना था, क्योंकि मामला पूरी तरह से 'परिवर्तन' अभिव्यक्ति के दायरे में आता है। इसलिए, संहिता के आदेश VI के नियम 17 के परंतुक का कोई प्रभाव नहीं था ताकि न्यायालय को उचित परिश्रम के बारे में संतुष्ट किया जा सके।

55. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के पास दिनांकित 27.07.2021 के आदेश की पुष्टि करने के लिए मजबूत कारण हैं।

56. नतीजतन, सरशियोरेराई रिट जारी करने की याचिका विफल हो जाती है।

57. स्थगन आवेदन का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है।

58. हालांकि, चुनाव न्यायाधिकरण चुनाव याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका के साथ पहले से दायर सत्यापन को पूरा करने की अनुमति देगा और फिर इसके साथ दायर सत्यापन करेगा। आवेदन दिनांक 09.04.2021, चुनाव याचिका के ज्ञापन के ठीक बाद ताकि यह प्रतीत हो कि वाद के आधार पर हो।

न्यायाधिपति दिनेश मेहता